

[श्री राम विलास पासवान]

दय नहीं देखा है। उसका पूरा जीवन एक सूर्यास्त है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। यह है हमारे देश का नक्शा।

पूरी दुनिया में जितने पशु हैं, उनमें से आधे पशु हमारे देश में हैं। लेकिन आज तक हम पशु बीमे की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। आज ही कृषि मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह, ने कहा कि जिसके पास अच्छी गाय है, वह जा कर बीमा करा ले। यह कोई जवाब है? अगर सरकार गांवों को ऊपर उठाना चाहती है, तो उसे पशुओं और फसल के बीमे की योजना बनानी पड़ेगी।

बाढ़ और सूखे से प्रति-वर्ष 800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, अर्थात् आजादी के बाद 30,000 करोड़ रु० का नुकसान हो चुका है। इस रकम से सरकार बड़ी से बड़ी योजना बना सकती थी। योजना मंत्री को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में रूरल डेवलप-मेंट का लक्ष्य रखना पड़ेगा। मेरा चार्ज है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यह देश कंगाल हो गया है। मेरे पूछने पर सरकार ने बताया कि गांवों में 70 परसेंट विद्युतीकरण हो गया है।

सभापति महोदय : अब आध घंटे का डिस्कशन होगा। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

17 30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Steps to increase Production of Groundnut

श्री राम लाल राही (मिसरिख): सभापति महोदया, सौभाग्य से आप सभापति की

चेयर पर बैठी हैं। हमारे ही जनपद से आप इस सभा में संसद-सदस्य चुन कर आई हैं। हमारे जनपद की समस्याओं से, वहां के किसानों की समस्याओं से और वहां की पैदावार से आप भली-भांति परिचित हैं। मैंने ग्राउंडनट के बारे में प्रश्न पूछा था। मेरे क्षेत्र में और मेरी जनपद के कई पड़ोसी जनपदों में मूंगफली की खेती की जाती है। आप जानती हैं कि सीतापुर उत्तर भारत की मूंगफली की प्रमुख मंडी रही है। इसके अलावा फरखाबाद साइड में भी कई जिले ऐसे हैं जिनमें मूंगफली अच्छी पैदा होती है। मुझे याद है कि जहां 1972-73 में सीतापुर के बाजार में प्रति दिन 70-80 हजार बोरी मूंगफली आती थी वहीं अब यह घट कर 7-8 हजार बोरी प्रति दिन रह गया है।

मैंने प्रश्न पूछा था—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान वर्ष वार और राज्यवार मूंगफली की प्रति हेक्टर पैदावार कितनी थी? यदि हां तो सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं।

(क) का उत्तर दिया गया है कि देश में मूंगफली के उत्पादन में उन वर्षों में जिनमें मौसम प्रतिकूल था, को छोड़ कर काफी बढ़ि हुई है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कमी होने के कारण हाल ही के वर्षों में उत्पादन में कमी आई है परन्तु 1983-84 में उत्पादकता गत वर्ष से अधिक रही है। अब उसके आंकड़े आपने दिए हैं—

उत्तर प्रदेश में सन 1981-82 में 261.4 हजार हैक्टर में मूंगफली बोई गई और उत्पादन हुआ 253.8 हजार टन। 1982-83 में 305 हजार हैक्टर में मूंगफली बोई गई और उत्पादन हुआ 187.2 हजार टन। मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा है 1983-84 को छोड़ कर। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 1982-83 में क्षेत्र बढ़ा है लेकिन उत्पादन कम हुआ है। जब 1982-83 में क्षेत्रफल बढ़ गया तो उत्पादन कैसे कम हो गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस फर्क की जानकारी उन्हें उत्तर प्रदेश से मिली है कि मूंगफली के उत्पादन में 1981-82 के मुकाबले में 1982-83 में गिरावट आई है? उन्होंने मौसम की खराबी का कारण बताया है। हमारे मूंगफली बोने का समय जुलाई से लिया जाता है और अक्टूबर में वह तैयार हो जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक कितनी बारिश हुई, यह मैं जानना चाहता हूँ? यदि बारिश ठीक हुई है, सही हुई है, तो 1981-82 के मुकाबले में 1982-83 में क्षेत्रफल बढ़ने के बाद पैदावार बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वह कैसे कम हो गयी। इसके लिए कौन कसूरवार है, सरकार कसूरवार है या किसान कसूरवार है या सरकार का प्रशासनतंत्र तो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, वह कसूरवार है? मूंगफली पैदा करने वाले किसान की मुख्य समस्या अच्छी क्वालिटी के बीज की है, जो उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो अच्छा बीज न मिलने की वजह से मूंगफली का उत्पादन गिर रहा है और दूसरी ओर उसकी जमीन का परीक्षण आपने नहीं किया है। आखिर मूंगफली का उत्पादन जो 1972-73 में कितना होता था, वह आज अब कम क्यों हो रहा है।

मैं आपको एक बात और बताना चाहता

हूँ। यह बात पिछले 17-18 सितम्बर की है। मेरी सचिव महोदय से मुलाकात हो गई, तो मैंने उनको कहा कि मूंगफली का उत्पादन गिर रहा है, इसको आपको देखना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि 22 एकड़ सिंचित क्षेत्र की बुआई से मुझे सिर्फ 14 बोरी मूंगफली का उत्पादन प्राप्त हुआ है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। मैं मंत्री जी को दावत देता हूँ और अविष्ठाता महोदय आपको भी, आप सीतापुर में उत्तर-प्रदेश के उन जिलों में जहां मूंगफली पैदा होती है, वहां का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको आंकड़ों की सूचना गलत दी जा रही है। हम जानते हैं आपका कृषि विभाग आंकड़े कहां से ले रहा है, लेकिन हम आंकड़े मार्केट से लेते हैं। उनको एकत्र करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मंडी समितियां बनाई गई हैं। मंडियों में कितना आदत हुआ और कृषि विभाग कितना कहता है, यदि आप इसको देखेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा और आप हमारी बात सही पायेंगे। मैं आप से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपको यह फर्क समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है, तो आप इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे? मेरा साफ मत है कि मूंगफली तिलहन के उत्पादन में एक बड़ा प्रमुख स्थान रखता है। वनस्पति घी बनाने में भी मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है। यदि मूंगफली का तेल वनस्पति बनाने के बजाय अगर उसको सीधे रिफाइनड

[श्री राम लाल राही]

करके इस्तेमाल किया जाए, तो ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन आपने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि इसका इस्तेमाल न हो। उसके बाद भी उत्पादन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि तेलों के दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

देश में एक हवा चली थी, मैं उसके व्योरे में नहीं जाना चाहता, चरबी-कांड के बारे में, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों तक तो वह हवा रही, इन्सान की मजबूरी पता नहीं क्या क्या करा ले, लोगों का मन बदला था कि चरबी मिला घी नहीं लेंगे, हम गाय-मांस नहीं खाते हैं, इसलिये गाय की चरबी मिला हुआ तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तेलों की बढ़ती हुई कीमतों ने उनको विवश कर दिया कि वे उसको खरीदें। चरबी मिलाने की बात तो सरकार ने खुद कही थी, फलां जैन और फलां वनस्पति उद्योग ने मिलाया था और वह पकड़ा गया। आपके ही पक्ष के लोग इसके बारे में बोले थे। उनकी इस मजबूरी के बावजूद भी लोगों को मंहगे दामों पर आज तेल खाना पड़ रहा है। इसलिये अगर मूंगफली का उत्पादन गिरेगा तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे।

मेरे जिले की हालत तो बहुत बदतर है। मैं कल ही निवेदन कर रहा था—हमारे यहाँ गन्ने की फसल में एक तरह का कीड़ा लग गया है जिसका ग्रेब और हापर नाम है। यह मूंगफली में भी लगता है, मूंगफली की पत्ती को नष्ट कर देता है। हजारों हैक्टेयर में यह कीड़ा लगा है। कम से कम चालीस किलोमीटर में तो मैं घूम कर आया

हूँ, खेत के खेत साफ होते चले गये हैं। एक तरफ गन्ने की बरबादी हुई है और दूसरी तरफ हजारों हैक्टेयर में जहाँ धान की फसल होती थी, पानी भर गया है, जमीनें पानी में डूब गई हैं। उसमें, अधिष्ठाता महोदय, आप का क्षेत्र ज्यादा है, मेरा बहुत कम है। मेरे जनपद की तो बड़ी अजीब दुर्दशा है—समझ लीजिये कि वह भुखमरी के कगार पर है।

इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ—क्या आप तेल की कीमतों को बढ़ते देख कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे मूंगफली की क्वालिटी और क्वाण्टिटी में सुधार हो? मैंने एक मांग की थी कि मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये सीतापुर जनपद में एक शोध सेन्टर कायम किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी उस बात को नहीं माना गया। मुझे आपकी सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया गया है कि कानपुर में शोध सेन्टर है। एरिया सीतापुर है, हरदोई, लखीमपुर और शाहजहांपुर है जहाँ हजारों क्विंटल मूंगफली पैदा होती है, लेकिन उसका शोध सेन्टर कानपुर में है जहाँ 20 टन भी पैदा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में इस शोध सेन्टर के बनाने का क्या फायदा है?

अभी रूरल डेवलपमेंट पर बहस हो रही थी। मैं पुनः कहना चाहता हूँ—आप गांवों को उपेक्षित रखे हुए हैं जिसकी वजह से कृषि उत्पादन के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ आज आपको अनाज बाहर से आयात करना पड़ा है, तेल आयात करना पड़ रहा है, गन्ने की जो स्थिति होने वाली है उससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में आपको चीनी भी आयात करनी पड़ेगी। यह आयात का काम

बन्द हो, इस दिशा में क्या कोई प्रयत्न आप करेंगे ताकि भारत का किसान तेल के उत्पादन में मूंगफली के उत्पादन में दिल-चस्पी ले ? उसके उत्पादन में जो गिरावट आई है उसको सुधारने के बारे में क्या आप कोई प्रयास कर रहे हैं ? और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, मैं जानता हूँ कि आप गुजरात के हैं और देश में जितनी मूंगफली होती है, सबसे अधिक गुजरात में मूंगफली होती है। गुजरात जो है, वह देश को बहुत हद तक तेल खाने को देता है लेकिन क्या आप चाहते हैं कि तेल के मामले में सारे प्रदेश गुजरात के भिखारी बने रहे। अगर आप उनको भिखारी बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर मुझे कुछ कहना है। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रदेश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो, तो इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। मैं आपको सारे देश के बारे में बताना चाहता हूँ। सन् 1981-82 में सारे देश में 72 लाख टन मूंगफली हुई और 1982-83 में 56 लाख टन हुई। इसके बाद 1983-84 में ऐसा लगता है कि इसकी पैदावार कम हो जाएगी। यह जो पैदावार है, इसमें उत्तर प्रदेश की पैदावार भी जुड़ी है। मैं आपको बताऊँ कि कल फरुखाबाद के कुछ लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनसे पूछा कि कल हाफ एन आवर डिस्कशन है और मूंगफली की पैदावार आप के यहाँ कैसी हुई है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मूंगफली की पैदावार बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गई है। वे कह रहे थे कि वह अब बिल्कुल पैदा नहीं होती है और इस तरह से वहाँ के उत्पादन में गिरावट आई है। उन्होंने यह भी बताया था कि फरुखाबाद के पास-पड़ोस के और जिलों में यह होती थी और उसके उत्पादन में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में अगर

मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप जानते ही हैं कि इस देश की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ की आबादी 10 करोड़ से अधिक हो गई है, 10 करोड़ लोगों के लिए अगर उनके अपने साधन से आप खाद्य तेलों को वहाँ से उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो आप उनको भिखारी रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप से कहना चाहूँगा कि क्या आप इस बात का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर भी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा हो। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं कर रही है, तो आपको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे तेलों के आयात करने की नीवत न आए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तेल की आयात की स्थिति में सुधार आए और आप आत्मनिर्भर हों, इसके लिए क्या आप समुचे उत्तर प्रदेश में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई सर्वे टीम भेजेंगे ? केन्द्र सरकार वहाँ पर एक टीम भेजे और वह वहाँ जा कर रिसर्च करे, महीने, दो महीने रहे और मैं तो कहूँगा कि पूरे सीजन वहाँ रह कर मिट्टी का परीक्षण करें और जो फसल बोई गई है, उसको देखें कि उत्पादन कैसा हो रहा है। क्या इस दिशा में आप विचार करने के लिए तैयार हैं ? अगर आप ऐसा करेंगे, तो मैं यह मान कर चलता हूँ कि इससे केवल सीतापुर की जनता पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सब लोगों पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

एक माननीय सदस्य : गुजरात का किसान बहुत मेहनत करता है।

श्री राम लाल राही : गुजरात का

[श्री राम लाल राही]
किसान अगर मेहनत करता है, तो सब जगह का किसान मेहनत करता है और पंजाब का किसान तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। आप उत्तर प्रदेश गये नहीं हैं। मैं आग के गुजरात घूम आया हूँ और मैंने देखा है कि आपके गुजरात में भी मेरे यहां जैसी जमीन है, जैसा मेरा क्षेत्र है, वैसे ही वहां का क्षेत्र है लेकिन मैं एक निवेदन कर दूँ कि उत्तर प्रदेश की पापूलेशन को देखते हुए, वहां इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको देखते हुए, वहां पर मूंगफली का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोग मेहनत न करते तो 1972-73 में कैसे 80 हजार बोरी प्रति दिन बाजार में कैसे भेजते। तब तक खेत को जा कर देखा, तो ऐसा लगता था कि जैसे खेत हरियाली से भरा हो। आज एक महीना हो गया है, पेड़ ज्यों का त्यों है। सिर्फ तीन-तीन, चार-चार पत्तियों का पेड़ दिखाई पड़ता है क्योंकि बोए तब जबकि बीज मूंगफली बने। सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। क्या आप ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि किसान पुनः मूंगफली बोने की तरफ आकर्षित हो और अगर आकर्षित हो तो आप कौन-कौन से उपाय करेंगे। इसके बारे में ब्योरे से बताइए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Madam Chairman, the hon. Member has mainly raised three points in the Half-an-Hour discussion and while initiating the debate on Half-an Hour he has reiterated these points again. So, I would like to confine myself to these points and give specific information to the hon. Member so that he can know that what he says is not true and is all unfounded. I would like to go one by one. He has said about all India, U.P. and particularly about

Sitapur because Sitapur is his constituency. The hon. Member has said that area under production of groundnut has gone down. That is not correct. The figures with me show that there is an increase in the area under cultivation of groundnut. I will confine myself to the figures from 1980 to 1984 because this Government came into power only in 1981. In 1980-81 the total oilseeds area under cultivation in Uttar Pradesh was 39.4 lakh hectares whereas the all India figure is 176 lakh hectares. This went up to 40.6 lakh hectares in 1981-82 and to 42.1 lakh hectares in 1982-83 in the case of U.P. whereas the all India figures for these two years are 190.5 lakh hectares and 191 lakh hectares respectively. If we talk of only groundnut, then so far as U.P. is concerned, the area under cultivation in 1980-81 was 1.91 lakh hectares which went up to 2.61 lakh hectares in 1981-82 and 3.05 lakh hectares in 1982-83. The all India figures for the area under groundnut cultivation are 68.01 lakh hectares in 1980-81, 72.4 lakh hectares in 1981-82 and 73.5 lakh hectares in 1982-83. The figure for 1983-84 is 76.2 lakh hectares. So, it will be seen that the area is on increase.

Now let me come to the production side. The production also has increased. The all India figure for oilseeds for the year 1980-81 was 93.7 lakh tonnes and the productivity was 5.32 quintals per hectare. The figures for oilseeds production in 1981-82 and 1982-83 are 121.9 lakh tonnes and 105.5 lakh tonnes respectively and the provisional figure for 1983-84 is 126.85 lakh tonnes. These are all India figures.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I think this is the figure for total oilseeds production.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : I have already said that these are the figures for total oilseeds production. Now, so far as U.P. is concerned, the production of oilseeds in 1980-81 was 16.5 lakh tonnes, in 1981-82 it was 17.1 lakh tonnes and in 1982-83, 16.5 lakh tonnes. Now there is a marginal fall in production

during 1982-83, because that was a drought year. As the hon. Member was pointing out, the crop of groundnut is from July to August. During this three-week period there was a prolonged dry spell, which damaged the crop of groundnut in U.P. and elsewhere also. I gave the all India figures for oilseeds.

Now I come to the figures of production of groundnut. In U.P. the figures of production of groundnut are :

1980-81	1.84	lakh	tonnes.
1981-82	2.54	"	"
1982-83	1.87	"	"

The fall is due to drought. The all India figure of groundnut production is :

1980-81	50.1	lakh	tonnes
1981-82	72.2	"	"
1982-83	55.5	"	"
1983-84	72.1	"	"

If you examine these figures, it is very easy to understand that not only the hectareage has gone up, but production and productivity have also gone up, so far as groundnut is concerned and so far as other oilseeds are concerned. Therefore, it is wrong to say that the area, production and productivity have come down, because the figures are very clear.

श्री राम लाल राही : मैंने यही कहा था कि आप कृषि विभाग के आंकड़े दे देंगे, लेकिन मैंने आपको जो कुछ बताया है वह मार्केट को देखकर बताया है। क्योंकि जितना उत्पादन होता है वह सब मार्केट में ही तो जाता है।

सभापति : ठीक तो है, ये कृषि विभाग के आंकड़े नहीं पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे।

श्री राम लाल राही : मैं यही तो कह रहा हूँ कि यदि आपको इन दोनों आंकड़ों

में फर्क लगे तो जिन लोगों ने आपको गलत आंकड़े दिए हैं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Mr. Chairman, you can understand my position. I have to go only by the information supplied by the State Government and my Ministry. I cannot go to the market and obtain the figures, as the hon. Member has perhaps done. What he says is unfounded.

श्री राम लाल राही : क्या आप गलत आंकड़े देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, क्योंकि आपको गलत आंकड़े दिए गए हैं। इसमें आपको कौन सी दिक्कत है, कह दीजिए कि नहीं करेंगे या कह दीजिए कि कार्यवाही करेंगे।

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is very clear that in this House no Minister can give wrong information, because it is nothing but branch of privilege. The hon. Member is within his rights to move a privilege motion against me, if I am giving wrong information.

The question asked is, what steps the Government have taken to increase the production of oilseeds in this country. There are a number of schemes which are being implemented at present for increased production of oilseeds.

In reply to the question, which was tabled by the hon. Member on 23rd July 1984, I have given the schemes. The Special Groundnut Development Project has been started in Gujarat since 1980-81 with an outlay of Rs. 35 crores. An Intensive Oilseeds Development Programme, covering groundnut also, was taken up in other potential States, including U.P., since 1980-81. In 1984-85 a comprehensive National Oilseeds Development Project, with 100 per cent financial assistance from the Government of India, has been taken up for implementation.

[Shri Yogendra Makwana]

Now, this project has two parts.

श्री राम लाल राही : जो 35 करोड़ खर्च कर रहे हैं इसमें से उत्तर प्रदेश में कितना आयेगा, जरा बता दीजिये ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सब आयेगा, आप जरा शान्ति रखें ।

Madam, the programme has the total outlay of Rs. 38 crores, for 1984-85 and it is 100 per cent assistance from the Government of India. No money is allocated from the State Budget. It is all from the Government of India.

Now, this project of Intensive Cultivation of Oilseeds is taken up for four major oilseeds—groundnut, soyabean, Sunflower, Rapeseed mustard oil. So far as the ground-nut project is concerned, it is in Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Orissa. In regard to Soyabean, it is in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh Rajasthan, Sunflower—Maharashtra Karnataka and Tamil Nadu. Rapeseed mustard oil—U.P. Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Assam, Gujarat and West Bengal.

The second part of this project is Intensive Oilseed Development Programme. It is for seven oilseeds—ground-nut is in Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh - where the Member comes from—Rajasthan and Punjab. Then rapeseed oil—Orissa, Punjab, Bihar, Jammu and Kashmir and Sikkim Soyabean—Gujarat, Himachal Pradesh, Bihar and Maharashtra. Sunflower - Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, West Bengal and Orissa. Niger seed—Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Safflower—Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh Sisamum i.e. Til oil—Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Karnataka. Now, this project is with the 100 per cent funds from the Government of India and this project is aimed at increasing production and productivity

of oilseeds in the country. The allocation of the funds under these schemes made to all-India and to Uttar Pradesh are sufficient. In the case of Uttar Pradesh it has increased. The Hon. Member was just now saying that less amount is allocated to Uttar Pradesh. That is not correct.

Now, I would refer to the figures in regard to the fund utilisation in oilseeds schemes and intensive oilseed development programme for ground-nut, rapeseed, mustard oil. I am referring to only U.P. and not to all India. In 1980-81 it was Rs. 74.16 lakhs. In 1981-82 it was Rs. 41.50 lakhs. In 1982-83 it was 140 lakhs and in 1983-84 it is Rs. 131.43 lakhs. Now, you can see from Rs. 74 lakhs it has come up to Rs. 131 lakhs. It is on the increasing side. But in 1984-85 there is a big jump from Rs. 131.43 lakhs, it has gone to Rs. 260.9 lakhs. Now, how can you say that funds allotted to Uttar Pradesh are less than other States? It has more than doubled—from 131 to 260.

The intensive oilseed development programme—Rs. 82.56 lakhs and under rapeseed mustard and soyabean and Safflower—178.33.

श्री राम लाल राही : लेकिन मूंगफली के बारे में बिल्कुल नहीं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मूंगफली आ गया आप सुनते नहीं हैं । यह जो दोनों स्कीमों हैं उसमें हैं । और मूंगफली के बारे में.....

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : What is the percentage of production of groundnut in U.P. to the national production figure ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : I can give figures of major oil seed crops in Uttar Pradesh.

Rapeseed oil, which is nearly 50 to 60 per cent of the total area in the country

comes from Uttar Pradesh. So far as production is concerned, it is 40 per cent production of the country.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : What about groundnuts ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is in scattered areas.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY . Is it something more than 2 per cent ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : I have no figure at present in terms of percentage. But I have got the figure for rapeseed and mustard oil and it is nearly 40 per cent of the total production of the country which comes from Uttar Pradesh.

The hon. Member has mentioned about Sitapur I will come to that part later on. But I would like to inform the hon. Member about Sitapur. Rahiji, you are very much concerned about Sitapur, your constituency.

प्रो० अजित कुमार मेहता : रामपुर में भी होता है क्या ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : होता है ।

In fact, we do not go to the district. But Rahiji is a very important Member of the House. (*Interruptions*).

Arrival of groundnut in Sitapur market: in 1981-82 : it was 95.6 thousand quintals. In 1982-83 it was 103.7 thousand quintals—this is for October to December, and the figure for 1983-84 is not available with me.

Now, I will tell about the area, production and yield of groundnut in Sitapur District. Let him know about it so that he can appreciate it. In 1982-83 the area under groundnut cultivation was 25,153 hectares and production was 14,639 tonnes. The yield per hectare

was 582 kg. The area under groundnut cultivation has increased from 25,153 hectares in 1982-83 to 28,860 hectares in 1983-84. Like that the production has gone from 14,639 tonnes to 19,088 tonnes. The yield per hectare which was 582 kg. during 1982-83 has gone up to 686 kg per hectare during 1983-84. So, how can you say it has declined ? The area has increased, the yield has increased and production has also increased in Sitapur and you are always shouting about Sitapur.

श्री राम लाल राही : मैं बिल्कुल कहता हूँ कि 100 फीसदी आंकड़े गलत हैं । मैं चेलेन्ज करता हूँ ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : He wants it to be like Sita—perfect.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Prof. Satyasadhan Chakraborty wanted the figure of groundnut in U. P. U. P. accounts for 2 per cent of the total production in the country.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is something more than 2 per cent.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : This is the figure I have got with me. It is wrong to say that area and productivity have gone down.

The second point of the hon. Member is about the schemes and allocation of funds. I have said, a number of schemes are there and I gave the amount which is allocated under the schemes to the entire country and U. P. also. Now, I am coming to the research part of it. The hon. Member says that there is no research and the farmers are suffering because of the low yielding variety, diseases and pests. This is not correct. There is one station in Mainpuri. It is not in Sitapur, but it is in Mainpuri. Mainpuri station is exclusively for groundnut. This station has developed two very good varieties. One is chandra and the second is...(*Interruptions*).

[Shri Yogendra Makwana]

The second is G 201. These are the two varieties which in ideal condition, if irrigated, gives nearly 25 quintals per hectare production. These are very high yielding varieties.

So far as G 201 is concerned, it is rust resisting variety. Pest disease does not effect it. This has replaced T 22 and M 37. This high pest resisting variety has developed in Mainpuri. So, it is wrong to say that research and development is not being done in this area.

The disease to which the hon. Member has repeatedly referred here in this House is white grub. An expert Committee consisting of the officers of the Government of India and those of the State Governments was appointed. This Expert Committee visited the fields and they conducted experiments also. They came to the conclusion that there is no grub in this area as claimed. Firstly, it is not there. If at all it appears in future, we have developed Integrated White Grub Management Programme. Now this programme is for the control of these pests. It has two parts —

1. Chemical spray. (2) Catching the beetle and killing it. This programme has also been developed by this Research Organisation where ICAR is mainly doing the work. So, it is wrong to say that no research has been done in groundnut and oil seed.

Now I come to seeds. He says seeds are not available. This is not correct. 25 quintals of breeder seeds of Chandra were produced, 10 quintals of G 201 breeder seeds were produced. It can be multiplied in the certified seeds. So far as production of certified seeds are concerned and distribution of certified seeds of groundnut are concerned, it is as under :—

Year	Place	Quintals
1982-83	U.P.	908
	All India	2,76,169
1983-84	U.P.	813
	All India	5,03,960
1984-85	U.P.	3000
	All India	5,14,649

So from 908 quintals it went to 3,000 quintals. How can you say that the certified seeds are not available? The certified seeds are available and available in a large quantity for the farmers.

Oil seeds mini kits are distributed for small and marginal farmers. In U.P. 3,11,476 mini kits were distributed.

This is what I have got from my Ministry. I can confidently say that it is unfounded if the hon. Member has said that the production, productivity area, everything has decreased. Oil is also decreased, no seeds are available, no research is done—this is all unfounded. There is no base in it. It is not true because I have given you the figure. I have given you the number of schemes. I have given you the amount which is given to the farmers.

Lastly, let me satisfy the hon. Member because his demand is for deputing a team of officers to his area. We did it. A team consisting of officers of the Ministry of Agriculture I.C.A.R., Directorate of Plant Protection and State Department of Agriculture visited Sitapur, Uttar Pradesh on 18-9-1983 to study the problem of groundnut production in Sitapur and the team has made six recommendations. All the recommendations are accepted by the Government and actions are being taken. If the hon. Member wants to know it, he can take it from me because it will take much time if I go on reading all the suggestions made and the action taken by the Government. I can say that six recommendations have been made by the team. The Government has accepted them and taken the action. So, it is not correct. Whatever the hon. Member has raised in the Half-an-Hour discussion is unfounded and far from the truth.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, only questions should be asked. No discussion is allowed.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) :
सभापति महोदय, मंत्री जी ने आंकड़ों के

द्वारा उसी तरह से सेटिस्फाइ करने की कोशिश की है जिस तरह से कोई बी० काम या एम० काम एकाउंटेंसी में लाखों का लेन देन दिखाकर किसी का तो दिवाला निकाल देता है और किसी को करोड़ों रुपए दिला देता है। उसी प्रकार से मंत्री जी ने भी आंकड़ों का प्रदर्शन किया है और उनके द्वारा संतुष्ट करने की कोशिश की है। मैं तो इससे क्या संतुष्ट होऊंगा जब माननीय राही जी ही संतुष्ट नहीं हुए हैं।

मूंगफली उत्तर प्रदेश में बदायूं, बरेली तथा अन्य जिलों में बालू वाली जमीन पर पैदा होती है जिस जमीन पर और कुछ पैदा नहीं होता। बदायूं, बरेली में जहां बहुत बड़ी मात्रा में मूंगफली पैदा होती थी, वहां पर पिछले तीन चार सालों से खेतों में हल तक नहीं जा सका है, मूंगफली का एक दाना भी नहीं बोया गया है। इसका कारण यह है कि किसान को रिटर्न नहीं मिल रहा है जिससे प्रोत्साहित होकर वह मूंगफली बो सके। बदायूं में हमारे यहां हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है जिस पर मूंगफली नहीं, पेठा मजबूरन बोना पड़ा है। पेठे की मिठाई आने आगरे में खाई होगी। जरा सी मूंगफली के स्थान पर दस किलो का पेठा पैदा कर रहे हैं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि मूंगफली की पैदावार बढ़ी है। यदि मूंगफली की पैदावार बढ़ी है तो गाजियाबाद में जैन शुद्ध वनस्पति द्वारा क्यों फैटरी को बंद करने की धमकी मजदूरों को दी जा रही है? अभी कल ही हमारे पास मजदूर आए थे। कारण यह है कि वनस्पति बनाने के लिए मूंगफली का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। मूंगफली से दूध जैसे आइ-टम्स भी तैयार किये जाते हैं। मिठाइयों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। मूंग-

फली की खली जानवरों को खिलाई जाती है। बिस्कुट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मूंगफली का उत्पादन कम होने की वजह से इन चीजों के उत्पादन में दिक्कत पैदा हो रही है। क्या मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि बदायूं, बरेली में मूंगफली क्यों नहीं पैदा हो रही है? मूंगफली की खेती के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मूंगफली की फसल को सिंचाई के मामले में वरीयता मिलेगी क्योंकि उसके अभाव में मूंगफली का दाना नहीं बढ़ पाता है? वहां पर सिंचाई में कुछ रियायतें दी जायें और जो बीमारियां फैल रही हैं उनकी जांच कराकर कि वे किन क्षेत्रों में फैल रही हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जाय।

मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसको सब खाते हैं, मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी उसको खाने हैं और बरबाद भी करते हैं। इस के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इसके भण्डारण की व्यवस्था के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी?

इसके जो साइड-उद्योग हैं बल्कि इसके ऊपर आधारित जो मुख्य उद्योग हैं—वह है वनास्पति तेल। पिछले दिनों जब हम काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गये थे तो सेना के अधिकारियों ने हमें बतलाया था कि वनास्पति घी का लोगों के हृदय पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो शुद्ध तेल इस्तेमाल करते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। इस लिये तेल का उत्पादन बढ़ाने तथा मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। मैं जानना चाहता

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]
हूँ कि मूंगफली से तेल उत्पादित करने में सरकार किस तरह से सहायता करेगी? क्या इस तरह की कोई सहायता सरकार करने जा रही है? जो कारखाने के मूंगफली के तेल में दूसरे तेल मिलाकर तथा उसमें चरबी मिलाकर वनस्पति घी पैदा करते थे, ऐसे कारखानों को सरकार बंद न होने दे तथा उनके लिये रा-मैटीरियल उपलब्ध कराये जिससे वहाँ के श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। क्या सरकार उनको तिलहन और जिन रा-मैटीरियल की जरूरत पड़ती है उपलब्ध कराती रहेगी?

सभापति महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता आप भी ऐसे ही प्रश्न पूछें जैसे कश्यप जी ने पूछे हैं, कोई लैम्बर न दें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (ममस्तीपुर) : मैं भाषण नहीं दूंगा, हम लोगों के अंश का भाषण राही जी दे चुके हैं।

सभापति जी, अभी मंत्री जी ने बतलाया है—1981-82 में मूंगफली का कुल उत्पादन 72.33 लाख टन और 1983-84 में 72.16 लाख टन, यदि मैं सही हूँ, हुआ है। इस फिगर को देख कर मेरी समझ में नहीं आया कि जैसा आपने दावा किया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, वह कैसे हुई है? जहाँ तक मेरी सूचना है—1981-82 में उत्पादकता का सूचक अंक था—136.9 और 1982-83 में यह 106.9 हो गया—तो यह उत्पादन कैसे बढ़ा?

दूसरी बात—अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसका असर बाजार पर भी पड़ता है। यदि मूंगफली का उत्पादन बढ़ा तो मूंगफली के उत्पादन से जो अन्य पदार्थ बनते

हैं, जैसे जमाया हुआ तेल—वनस्पति घी—उस की कीमत कैसे बढ़ गई? अगर उत्पाद बढ़ा है तो कीमत रीजनेबिल होनी चाहिए, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिये। लेकिन जमाये हुए वनस्पति तेल की कीमत 1 रु० 40 पैसे प्रति के० जी० बढ़ा, जिसका मतलब है कि बाजार में दो रुपये प्रति के० जी० के हिसाब से बढ़ गया। यह तो सरकारी रेट है, लेकिन इसका असर बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता हूँ कि जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसका असर सामान्य जनता पर क्यों नहीं पड़ता है। इसलिए हमको आंकड़ों पर अधिक विश्वास नहीं हो रहा है। यदि आप इसके बारे में कुछ खुलासा करें तो हमारी ज्ञान वृद्धि होगी।

आपने बताया है कि 1981-82 में नौ राज्यों में मूंगफली विकास की परियोजनाएँ चलाई गईं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या परिणाम निकला? अंत में मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने 1984-85 में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चलाई है, तो इस परियोजना में बिहार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके क्या कोई परिणाम सामने आए हैं कि इससे क्या लाभ होने जा रहा है?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि पिछले एक अप्रैल से तिलहन विकास परिषद् और राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू की है और उसी दौर में सरकार ने रिकार्ड उत्पादन किया है। मैं मूंगफली के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तिलहन के बारे में कह रहा हूँ। हमने

1200 करोड़ रु० खर्च करके 14 लाख का आयात किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हमको 40 अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा, अगले पांच सालों में तेल के आयात पर। हमने पिछले बीस वर्षों में तिलहन की प्रगति दो प्रतिशत के हिसाब से की है। उत्तर प्रदेश मूंगफली का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 448 किलो है, जबकि विश्व का औसतन 917 है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना फर्क है। भारत में प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन 752 के० जी० है, चीन में 1150 है, नाइजेरिया में 1615 है और अमरीका में 1425 है और 25 लाख टन तेल हम उत्पादन करते हैं। आप यह जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन में सबसे बड़ी भूमिका किसान की है। जब वह पैदा करेगा, तब आपके तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई समर्थन मूल्य घोषित करने जा रहे हैं, ऐसी कोई नीति बनाने जा रहे हैं? जैसे कि आने गेहूँ का समर्थन मूल्य घोषित किया है, तिलहन का भी समर्थन मूल्य घोषित कर दीजिये, जिससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन करे। नहीं तो बाजार में क्या होता है कि मूंगफली का तेल 30 रु० बिकता है और किसान को उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसलिए आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

SHRI YOGENDRA MAKWANA :
This Half an-Hour Discussion was confined only to Uttar Pradesh. Because the hon. Member Mr. Ram Lal Rahi comes from Sitapur, I got the figures from Sitapur Districts... (Interruptions). I am prepared to give for U.P. The Government of India can give only State figures. If you ask for the figure in respect of your village it will not be available with me. So, I can give the figures of the

State. But because he is from Sitapur, we brought the figures in respect of Sitapur also. So far as Badayun and Bareilly districts are concerned, I have no information about the groundnut cultivation there, about the production, acreage and other things. You can understand that groundnut is not the main crop so far as oilseeds are concerned in U.P. As I said, it constitutes only two per cent of the entire production of the country. The main crop is rapeseed mustard oil; it produces nearly 40 per cent of the total production of the country and the area is also nearly 60 per cent of the entire country's area. So, U.P. can contribute in the production of rapeseed mustard oil and other oilseeds, but not in groundnut, as the groundnut-growing States are contributing.

The hon Member wanted to know why, when the production has increased, the price has increased. Production is not the only thing which is counted in price. The price depends on a number of factors; the demand-and supply is also one such factor; if the supply is less and the demand is more, than the price will go up; the normal law of economics will prevail. Then there is inflation. If you see the price index from 1970-71, you will find that today the price index, if I am not wrong, has gone up to 328 per cent - all commodities put together...

PROF. AJIT KUMAR MEHTA :
You have said that the production has increased, In 1981-82 it was 72.33 lakh tonnes and in 1983-84 it was 72.6 lakh tonnes. When the production has remained the same and the acreage has increased, it means that the productivity has fallen

SHRI YOGENDRA MAKWANA :
From 55.5 lakh tonnes in 1982-83 the production has gone up to 72.1 lakh tonnes. This is the all India figure

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I said about 1981-82. In 1981-82 it was 72.33 lakh tonnes and in 1983-84 it was 72.16 lakh tonnes...

SHRI YOGENDRA MAKWANA :
It is more or less the same.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : But the acreage has increased.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It was 74.29 lakh hectares and it had gone up to 76.2 lakh hectares.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : The acreage has increased, but the production is the same. That means, the productivity has fallen.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : There is a marginal decline. The production was 72.3 and it came down to 72.1. The acreage has increased from 74.29 lakh hectares to 76.2 lakh hectares. So, there is a marginal decline. But agriculture is such a field where production cannot be consistent. If you take the overall oilseed production, then you will find that the oilseed production has gone up: in 1981-82 it was 122.9 lakh tonnes and it has gone up to 125.85 lakh tonnes. There is a marginal increase in acreage. But the overall oilseed production has gone up. In groundnut there is a marginal decline. But all oilseeds put together it has gone up. So it is wrong to say that it has decreased.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : Then why has the index number of productivity fallen?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Per hectare it has gone up to 661 from 640. It has increased. Only in groundnut there is a marginal decline. So it is not correct to say like that. There are

a number of schemes which I have just narrated, I do not want to go into them again and again and repeat it.

Then about the support price the hon. Member wanted to know. The Government have declared the support price of oil seeds. In 1980-81 it was Rs 206 per quintal. In 1981-82 it was Rs. 270. In 1982-83 it was Rs, 295 and for 1983-84 the support price was Rs 315. So it has increased from Rs 206 to Rs. 315 per quintal. About the schemes there is one more scheme that is done by the National Oilseeds Development Board for improving the productivity and production of seeds.

श्री राम लाल राही : मैं सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने जो सवाल उठाये थे, उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वे निराधार हैं, तथ्यों से परे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आपको गलत इफॉर्मेशन दी है, क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? अन्यथा मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब भाषण देते हैं तो सुनते भी हैं और देखते भी हैं लेकिन जब वे जवाब देते हैं तो न सुनते हैं न देखते हैं, केवल कागज ही देखते हैं।

18.38 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 6th August, 1984/Sravana 15, 1906(S).